

“सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन”

¹टिंकू सैनी, ²डॉ. मौसम पारीक

¹(पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षा संकाय)

अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

²(सहायक आचार्या) अपेक्स विश्वविद्यालय

शोध सार

आजादी के बाद भारतीय शिक्षा की अवधारणा में भी संविधान में वर्णित मूल्यों, आदर्शों और प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तन किए गए और शिक्षा को संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया। आजादी के पश्चात् शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया जिन्होंने अपने-अपने स्तर पर शिक्षा व्यवस्था के सम्बंध में अपना-अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि इतने वर्षों के प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में विकास तो हुआ ही है लेकिन साथ ही कई चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में शिक्षा का स्तर काफी निम्न हो गया था जिसके परिणामस्वरूप भारत में साक्षरता का प्रतिशत भी अत्यधिक कम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में संविधान लागू होने के बाद कृषि, विज्ञान, रक्षा जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति और विकास हेतु कई प्रावधान किए गए। किसी भी देश की सरकार अपने क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सरकारी विद्यालयों की स्थापना करती है। साथ ही निजी क्षेत्र को भी शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अवसर प्रदान करती है जिससे न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि निजी स्तर पर भी शिक्षा के भरपूर अवसर प्रदान किए जा सकें। इस क्रम में देश के समस्त विद्यालय एवं उनमें कार्यरत शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकारी विद्यालयों के अपेक्षा निजी विद्यालयों में शिक्षा के प्रति सुधार अधिक देखने को मिलते हैं। तथापि भारत की स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षा के सरकारी क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। आवश्यकता के अनुसार इन परिवर्तनों से न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ा है बल्कि आज का युवा अपनी विद्वता का परचम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी फहरा रहा है।

अधिकांश विद्यालय अब शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और नवीनतम ज्ञान के माध्यम से, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से एवं नवाचार के माध्यम से न केवल निजी विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं बल्कि उन्हें पीछे भी धकेल रहे हैं। इसका कारण सरकार का सरकारी विद्यालयों की तरफ ध्यान देना है और सरकारी विद्यालयों की सभी व्यवस्थाओं में सुधार करना है।

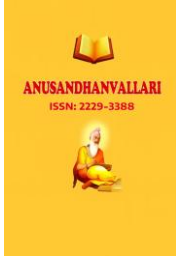
मुख्य शब्दावली

सरकारी विद्यालय, शिक्षा व्यवस्थाएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी आदि।

➤ प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में उस देश के अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यापक राष्ट्र की एक ऐसी नींव तैयार करते हैं जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र अपने होनहार विद्यार्थियों की मदद से प्रगति के सोपान को प्राप्त करता है। आज किसी भी देश का निर्माण उसकी कक्षाओं में योग्य अध्यापकों के द्वारा होता है। अर्थात् किसी भी देश के विद्यार्थी के निर्माण एवं विकास में अध्यापक तभी भाग ले सकते हैं, जब उनकी शिक्षा उनकी रुचियों एवं अभियोग्यताओं के अनुसार हो, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ उसे विकासोन्मुखी प्रगति की ओर गतिमान करते हुए उसमें धैर्य, विवेक, सहिष्णुता, सुसम्पन्नता, बौद्धिक एवं सामाजिक सफलता आदि ऐसे मानवोचित गुणों से अलंकृत करते हुए जीवन जीने की कला सिखाती है।

इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर जिले के सरकारी विद्यालयों की भौतिक व्यवस्थाओं, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों एवं उपलब्धियों का पता लगाने हेतु भोधार्य द्वारा एक भोधकार्य किया गया है। प्रस्तुत लेख में सरकारी विद्यालयों की वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाओं के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के विचारों एवं उनके अभिमतों को आधार बनाकर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।



➤ **समस्या का औचित्य**

प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में विद्यालय का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान था जितना कि किसी भवन में उसकी नींव का होता है। परम्परागत एवं उन्नत समाजों में तो यह कार्य परिवार, समुदाय आदि अनौपचारिक अभिकरणों के माध्यम से भी किया जा सकता है, किन्तु भारत जिस प्रकार के नवीन समाज की संरचना करना चाह रहा है, जिस संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है वहाँ विद्यालय से अधिक उपयुक्त अन्य कोई अभिकरण नहीं है। परन्तु वर्तमान समय में विद्यालय व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ पाई जाने लगी हैं। यदि हम अलग-अलग विद्यालयों का अवलोकन करें तो हम यह पायेंगे कि यदि एक विद्यालय के कर्मचारी विद्यालय कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं या अपने आपको विद्यालय का अभिन्न अंग मानते हैं तो वहीं दूसरे विद्यालय में कर्मचारी मात्र औपचारिकता का निर्वाह करते हुए कार्य करते हैं और विद्यालय के कार्यक्रम में उनका कोई योगदान नहीं होता है।

अपितु प्रत्येक सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाओं के प्रति वहाँ कार्यरत अध्यापक-अध्यापिकाओं एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में भी भिन्नता होती है। उक्त कथन की वास्तविकता का पता लगाने के लिए शोधार्थी द्वारा पूर्व में किए गए विभिन्न शोध कार्यों का अध्ययन किया गया जिसमें भोधकर्ता को पता चला कि सरकारी विद्यालयों की समस्त व्यवस्थाओं के प्रति सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से सम्बन्धित कोई उपयोगी अध्ययन नहीं हुआ है और न ही इस विषय से सम्बन्धित कोई शोधकार्य वर्तमान में देखने को मिला है।

सरकारी विद्यालयों की विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता और शिक्षकों व विद्यार्थियों के सहसम्बन्ध का सन्दर्भ, जीवन से जुड़ा है। शोधार्थी के दृष्टिकोण में यह समस्या नवीन, समसामयिक व शोधकार्य करने हेतु उपयुक्त है। अतः शोधार्थी को इसके अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी को देखते हुए शोधार्थी ने उक्त समस्या का चयन किया जो कि प्रासंगिक एवं विषय से सम्बन्धित भोधकार्य हेतु उपयोगी हो सकती है। फलतः शोधार्थी ने इसे अपने अध्ययन का विषय बनाया।

➤ **समस्या कथन**

“सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन”

➤ **समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण—**

- **सरकारी विद्यालय**— सरकारी विद्यालयों से अभिप्राय राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित, नियंत्रित एवं प्रायोजित समस्त प्रकार के सरकारी विद्यालयों से है।
- **शिक्षक**—राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त प्रकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक।
- **विद्यार्थी**— विद्यार्थी से अभिप्राय विद्यालयों में पढ़ने वाले उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों से लिया गया है।
- **भौतिक व्यवस्था**—भौतिक व्यवस्था किसी भी संगठन का आधार होती है इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आधारभूत ढांचागत संसाधन शामिल हैं।

➤ **शोध उद्देश्य:—**

1. सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति महिला व पुरुष शिक्षकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति छात्र व छात्राओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

➤ **भोध परिकल्पनाएं :-**

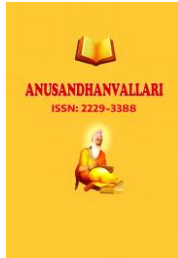
1. सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति महिला व पुरुष शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति छात्र व छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

➤ **चर :-**

शोध को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने में चर की अहम भूमिका होती है। ये परिवर्तनशील होते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं —

स्वतन्त्र चर : सरकारी विद्यालयों की भौतिक व्यवस्थाएँ।

आश्रित चर : शिक्षक एवं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण।



➤ शोध विधि:-

प्रस्तुत शोधकार्य में समस्या की प्रकृति, उपयोगिता एवं क्षेत्र का देखते हुए अनुसंधान कार्य हेतु **सर्वेक्षण विधि** का प्रयोग किया गया है।

➤ शोध की जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में जयपुर जिले के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में लिया गया है।

➤ न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा जयपुर जिले के उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों के 50 शिक्षक एवं 100 विद्यार्थियों को लिया गया है।

➤ शोध के उपकरण :

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शिक्षकों व छात्रों के दृष्टिकोण को ज्ञात करने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अभिमतवली का प्रयोग किया गया है।

➤ शोध का परिसीमन-

1. प्रस्तुतशोध अध्ययन को राज्य सरकार द्वारा संचालित जयपुर जिले के सरकारी विद्यालयों तक सीमित रखा गया है।
2. शोध अध्ययन को राज्य सरकार द्वारा संचालित जयपुर के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया है।

➤ शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी-

मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात।

➤ आंकड़ों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना-1

सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति महिला व पुरुष शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या 1

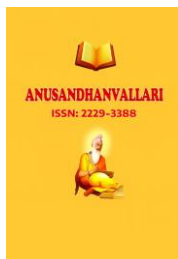
शिक्षक समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात
महिला	25	16.15	2.39	0.04
पुरुष	25	16.12	2.36	
कुल	50	32.27	4.75	

स्वतंत्रता के अंश (df) = 48 (50 - 2)

0.05 स्तर पर सारणीमान = 1.676

0.01 स्तर पर सारणीमान= 2.403

विश्लेषण एवं व्याख्या- तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण के प्राप्तांकों का मध्यमान 32.27 है तथा पूर्ण समूह का मानक विचलन 4.75 है। प्राप्तांकों का क्रान्तिक अनुपात 0.04 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 48 हेतु 0.05 सार्थकता स्तर व 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान 1.676 व 2.403 से कम है। अतः उक्त परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति महिला व पुरुष शिक्षकों के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

**परिकल्पना-2**

सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति छात्र व छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

सारणी संख्या 2

विद्यार्थी समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात
छात्रा	50	30.50	6.6895	0.9577
छात्र	50	29.17	7.1975	
कुल	100	59.67	13.887	

स्वतंत्रता के अंश (df) = 98 (100-2)

0.05 स्तर पर सारणीमान = 1.984

0.01 स्तर पर सारणीमान = 2.624

विश्लेषण एवं व्याख्या- तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति छात्र-छात्राओं के दृष्टिकोण के प्राप्तांकों का मध्यमान 59.67 है तथा पूर्ण समूह का मानक विचलन 13.887 है। प्राप्तांकों का क्रांतिक अनुपात 0.9577 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 987 हेतु 0.05 सार्थकता स्तर व 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान 1.984 एवं 2.624 से कम है। अतः उक्त परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति छात्र-छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

➤ निष्कर्ष**परिकल्पना-1**

सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति महिला व पुरुष शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष-1

उपर्युक्त परिकल्पना का सांख्यिकी विश्लेषण करने के उपरान्त निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति महिला व पुरुष शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना-2

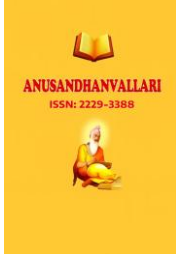
सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति छात्र-छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष-2

इस परिकल्पना का सांख्यिकी विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी विद्यालयों के भौतिक संसाधनों के प्रति छात्र-छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

➤ शैक्षिक निहितार्थ

- आज के आधुनिक समाज में जहाँ शिक्षा की व्यवस्था उच्च से उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए वहाँ आज भी सरकारी विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। इस स्थिति को निरंतर प्रयास द्वारा सुधारा जा सकता है।
- अधिकांश विद्यालय अब शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और नवीनतम ज्ञान के माध्यम से, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से एवं नवाचार के माध्यम से न केवल निजी विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं बल्कि उन्हें पीछे भी धकेल रहे हैं। इसका कारण सरकार का सरकारी विद्यालयों की तरफ ध्यान देना है और सरकारी विद्यालयों की सभी व्यवस्थाओं में सुधार करना है।
- वैसे भी कहा गया है कि “जहाँ चाह होती है, वहीं राह होती है।” बस सरकार को अपनी चाह को मजबूत करना होगा ताकि देश का भविष्य जो कि विद्यालयों में विकास कर रहा है उसके विकास में गति के पर लग जायेंगे।
- सरकार यदि सरकारी विद्यालयों की आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखकर अपने कदम उठाए एवं निर्धारित भौक्षणिक योजनाओं को तय समय पर पूर्ण करने का लक्ष्य रखे तो सरकारी विद्यालयों की भौक्षणिक व्यवस्थाओं में जो सुधार आयेगा वो लम्बे समय तक देश को अपने योगदान से परिपूर्ण करेगा।



➤ **भावी शोध हेतु सुझाव**

1. राजस्थान राज्य के अन्य सरकारी विद्यालयों की भौतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है।
2. निजी एवं सरकारी विद्यालयों की भौतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. सरकारी विद्यालयों की प्रगति एवं विकास का अध्ययन किया जा सकता है।
4. राज्य का अन्य राज्यों अथवा सम्पूर्ण देश की शैक्षिक व भौतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
5. देश/राज्य में विभिन्न बोर्ड द्वारा प्रशासित एवं संचालित सभी प्रकार के सरकारी एवं निजी विद्यालयों की शैक्षिक एवं भौतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक एवं विशलेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ-ग्रन्थ

1. बेस्ट जॉन डब्ल्यू "रिसर्च इन एजुकेशन", प्रेविटस हॉल, (इंक) ऐंगिल बुक विलफस, यू.एस.ए.।
2. भटनागर ए. बी. व भटनागर मीनाक्षी (2016) : "भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास", आर.लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. चौहान आर.एस. अग्रवाल एस. के. (2015) : "शिक्षा एवं शिक्षण सिद्धान्त", साहित्य प्रकाशन आगरा।
4. कन्चलडॉ. रितु शर्मा डॉ. मधुबाला व शर्मा डॉ. सूरजमल (2014) : "भारतीय समाज और शिक्षा", शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
5. प्रजापति सुरेश कुमार (2006) : "शैक्षिक प्रबन्ध एवं विद्यालय संगठन", गोयल पब्लिकेशन, जयपुर।
6. रुहेला प्रो. सत्यपाल (2008): "शिक्षा के सामाजिक आधार", माया प्रकाशन मंदिर, जयपुर।
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-2005), एनसीईआरटी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समाचार पत्र जनवरी-फरवरी (2025) दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण, जयपुर।
9. समाचार पत्र जनवरी-फरवरी (2025) राजस्थान पत्रिका, जयपुर संस्करण, जयपुर।
10. समाचार पत्र जनवरी-फरवरी (2025) नवभारत टाइम्स, जयपुर संस्करण, जयपुर।
11. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, (RTE-2009), एनसीईआरटी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. वेदप्रकाश (2008) : "विद्यालय संगठन एवं नवीन शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, कल्पना पब्लिकेशन, जयपुर।
13. वेदप्रकाश, शर्मा वन्दना (2008) : "आधुनिक भारत में शिक्षा", कल्पना पब्लिकेशन, जयपुर।